कोटद्वार, गुरूवार
21 अगस्त 2025
वर्षः 47
अंकः 109 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

केदारनाथ हाईवे पर सेमी में बन रहा खतरा

रुद्रप्रयाग : जनपद में हो रही झमाझम बारिश और इसके बाद निकल रही तेज धूप से अब सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है। रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास में कई जगहों पर भू-धंसाव हो रहा है जिससे लगातार मुश्किलें बढ़ सकती है। जबकि केदारनाथ हाईवे में भी सेमी के पास अब भी खतरा पैदा कर रहा है। यहां नदी से लगातार कटाव जारी है। मुख्यालय स्थित जवाड़ी बाईपास के मध्य स्थल पर लगातार भू-धंसाव हो रहा है। बीते दिनों पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग तीन दिनों तक बंद रहा। जबकि पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित पार्क के करीब हाईवे पर धंसाव हो रहा है। सड़क पर अलग-अलग स्थानों पर हो रहे धंसाव से लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। इस सड़क पर पूर्व में भी कई बार धंसाव हुआ किंतु स्थाई ट्रीटमेंट आज तक नहीं हो सका है। एक ओर नदी किनारे से पहाड़ी पर कटाव जारी है तो वहीं दूसरी ओर दरकती पहाड़ी में रोकथाम के पुख्ता इंतजाम न होने से यहां लगातार सड़क सिंक हो रही है। जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग नगर का एकमात्र बाईपास है जिससे बड़ी संख्या में वाहनों का संचालन किया जाता है। यदि बाईपास का जल्द बेहतर ट्रीटमेंट न किया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे पर सेमी में लगातार खतरा बना है। यहां हाईवे पर अंदरुनी तरफ से धंसाव जारी है जबकि पुश्ता भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। हालांकि पुश्ता निर्माण का काम तो किया जा रहा है किंतु नदी के कपाट से खतरा लगातार बना है। हाल ही इस सड़क पर मोटी धनराशि भी खर्च की गई है। इधर, एनएच लोनिवि के ईई ओंकार पांडेय ने बताया कि सेमी में सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। जबकि जवाड़ी बाईपास पर भी स्थिति का निरीक्षण करते हुए ट्रीटमेंट की कार्यवाही की जाएगी।

विपक्ष ने जन आकांक्षाओं का गला घोंटा है: महाराज

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था। लेकिन विपक्ष ने हंगामे और सदन की कार्यवाही में बार अवरोध खड़े कर सदन की मर्यादा को तार-तार करने के साथ-साथ विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल रहा है। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सदन में विपक्ष का जो आचरण रहा है वह घोर निंदनीय था। विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा चाहता था, लेकिन खुद नियम-कानून का पालन करने को तैयार नहीं था। निकाय चुनाव और हाल ही में संपन्न राज्य के 10 पंचायत निकायों के चुनावों में भाजपा को मिले जनादेश से विपक्ष निराशा और हताशा में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहाड़ के हितों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप मानसून के दौरान गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया लेकिन विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हितों को तिलांजलि देकर सदन को नहीं चलने दिया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार, लगातार हंगामे एवं अवरोध खड़े करने से उसने जन आकांक्षाओं का गला घोटने का काम किया है उसके इस कृत्य से असमय सत्रावसान हुआ नतीजतन प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया।

खराब नेटवर्क से कई गांवों के लोग परेशान

रुद्रप्रयाग : केदारघाटी के कई गांवों में नेटवर्क की परेशानी के चलते उपभोक्ता परेशान हैं। देवली भणिग्राम, लमगोण्डी, फली पसालत, सिंगोली, ल्वारा, ल्वाणी, सल्या, तुलंगा, अन्द्रवाड़ी, सांग, तिनसोली, लुहैड़ा, सुभदिनी, नाग जगई सहित क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों में निजी, बीएसएनएल किसी भी कंपनी का नेटवर्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जिससे लोगों को नेटवर्क के लिए घर से बाहर आना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने सभी कंपनियों से नेटवर्क को बेहतर करते हुए सेवा को ठीक तरह से संचालित करवाने की मांग की है। जिपंस सुबोध बगवाड़ी, पूर्व जिपंस केशव तिवारी, पूर्व जिपंस गणेश तिवारी ने कहा कि कंपनियों के नेटवर्क में गड़बड़ी से लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही है। (एजेंसी)

लोकसभा में पेश हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयक

लोकसभा में विपक्ष ने अमित शाह पर कागज के गोले फेंके, सुरक्षा में दौड़े मार्शल

नई दिल्ली , केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच तीन बिल पेश कर दिए। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गंभीर अपराध के आरोप लगने और 30 दिनों तक जेल जाने की स्थिति में उन्हें उनके पद से हटाया जा सकेगा। बिल पेश करते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के सामने उछाल दी। ये घटना उस वक्त हुई जब केंद्रीय मंत्री लोकसभा में एक सौ तीसवां संशोधन विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश किया। वही, केंद्र ने विपक्षी सांसदों पर निशाना साधा। केंद्र ने विपक्ष के आचरण पर आपत्ति जताई और कहा कि सांसदों को जनादेश का अनादर नही करना चाहिए तथा बहस और चर्चा में योगदान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा,इजनता हमें काम करने के लिए भेजती है, क्या विपक्ष हंगामा करने आता है? लोकतंत्र का अपमान करने वालों को देश की जनता माफ नही करेगी। सांसदों को जनादेश का अनादर नही करना चाहिए और बहस और चर्चा में योगदान देना चाहिए।

नईदिल्ली ,। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से जुड़े 3 विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रावधान हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन में पेश किया। बता दें कि हाल ही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से ही पद संभाला था। इसी के बाद ये विधेयक लाए गए हैं। गृह मंत्री ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की सिफारिश की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई थी?

इस पर गृह मंत्री ने कहा, मुझ पर जब आरोप लगे थे तो मैंने गिरफ्तारी से पहले नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था। कोर्ट से निदोष साबित न होने तक मैंने कोई सांविधानिक पद नहीं लिया था। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं इन विधेयकों का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए संविधान संशोधन किया जा रहा है।

दिल्ली के 50 से अधिक स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, दहशत फैली

नईदिल्ली,दिल्ली के 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 48 घंटे बाद फिर से 50 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मालवीय नगर स्थित एसकेवी हौज रानी और करोल बाग स्थित आंध्रा स्कूल समेत 50 स्कूलों को बुधवार सुबह अज्ञात ईमेल मिले हैं। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुंच गई। परिसर खाली करा लिया गया है। धमकी की सूचना के बाद पुलिस ने स्कूल परिसर को खाली करा दिया, जबकि कुछ बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। अभी कुछ स्कूलों की तलाशी चल रही है, जबकि कुछ स्कूलों में संदिग्ध सामान नहीं मिला है। इससे पहले सोमवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:25 बजे के बीच 32 स्कूलों ने पुलिस को फोन करके ईमेल पर धमकी मिलने की जानकारी दी थी। सोमवार को पूरे दिन तलाशी में कुछ नहीं मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी से अब तक दिल्ली-एनसीआर के 74 शैक्षणिक संस्थानों, 70 स्कूलों और 4 कॉलेजों को बम से उड़ाने धमकियां मिल चुकी हैं।

मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

●सजा पर रोक के साथ विधायकी भी बहाल

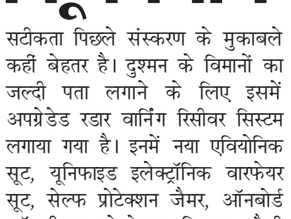

प्रयागराज , मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है और अब मऊसदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा। न्यायमूर्ति समीर जैन ने आज यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इससे पहले 30 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब्बास अंसारी की तरफ से वकील उपेंद्र उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने सजा पर रोक लगाने का पुरजोर विरोध किया था। मामला 2022 के विधानसभा चुनाव का है, जब अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान कथित तौर पर सरकार बनने पर अधिकारियों से 'हिसाब-किताबझ् करने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ भाषण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 31 मई, 2025 को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस सजा के आधार पर 1 जून, 2025 को विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी रद्द करते हुए मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास ने पहले मऊ की जिला अदालत में अपील की थी, लेकिन 5 जुलाई को वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा उपराष्ट्रपति पद का पर्चा, 9 सितंबर को है चुनाव

नई दिल्ली,उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के समय उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई कद्दावर नेता और अन्य सांसद उनके साथ पर्चा दाखिल करने के समय पहुंचे. बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन पत्रों के पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक थे. नामांकन 4 सेटों में दाखिल किया गया. प्रत्येक सेट में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर थे. पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे, जबकि बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ एनडीए नेताओं के हस्ताक्षर थे. इस तरह से ये गठबंधन में व्यापक सहमति को दर्शाता है. इस तरह से इस ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से सीपी राधाकृष्णन की सीधी टक्कर होगी.

संसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित एनडीए के लगभग 160 सदस्य मौजूद थे. गौर करें तो सीपी राधाकृष्णन को नामित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सर्वसम्मति से लिया गया था. एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सर्वसम्मति से मिले समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी उपस्थित नेताओं ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के लिए अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया था. इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन के योगदान की सराहना की और उन्हें विनम्रता, बुद्धिमत्ता और जमीनी स्तर से जुड़ाव वाला नेता बताया.

सोशल साइट पर एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, पीएम मोदी ने कहा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से खुद को प्रतिष्ठित किया है. उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, कैंप कार्यालय में कर रही थीं जनसुनवाई

नईदिल्ली,दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। यह हमला उन पर तब हुआ, जब वह सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको थप्पड़ भी मारा। इस दौरान काफी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 41 वर्ष का राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का एक रिश्तेदार जेल में है और वह उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। इस संबंध में वह अपना पत्र लेकर मुख्यमंत्री के पास आया था। यह मामला कोर्ट में लंबित है। दिल्ली पुलिस आरोपी के बारे में और अधिक पता करने के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क में है। जनसुनाई में मौजूद अंजली रमेजा ने बताया, जब यह घटना हुई, तब वह मुख्यमंत्री लोगों को सुन रही थीं। हमें पीछे से शोर सुनाई दिया, और जब तक हम मुड़े, पुलिस हमलावर को पकड़ कर ले जा चुकी थी। पत्रकार ने उनसे थप्पड़ मारे जाने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हां, उनके ऊपर हमला हुआ था और रेखा जी पूरी तरह सदमे में थीं। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अचानक से हमला हो गया, जो गलत है। सूत्रों ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री पर पर एक भारी वस्तु फेंकी गई, जिससे वह जमीन पर गिर गईं थीं।

भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 नए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमान

–केंद्र ने खरीद को दी मंजूरी

नईदिल्ली , भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 97 एलसीए तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि एक उच्चस्तरीय बैठक में विमानों की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। 62,000 करोड़ रुपये की लागत से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इन विमानों का उत्पादन करेगा।

नए ऑर्डर के बाद वायुसेना में तेजस विमानों की कुल संख्या 180 हो जाएगी। इससे पहले वायुसेना ने 83 तेजस विमानों का ऑर्डर करीब 48,000 करोड़ रुपये में दिया था। ये नए विमान मिग-21 विमानों की जगह लेंगे। बता दें कि मिग-21 विमान पुराने हो चुके हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं। इसी वजह से इन्हें चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से बाहर किया जा रहा है। मिग विमानों को 19 सितंबर को सेवानिवृत्त किया जाएगा। तेजस मार्क 1ए मौजूदा तेजस विमानों का आधुनिक संस्करण हैं। इसमें बेहद ताकतवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है, जो एक साथ कई लक्ष्यों और ठिकानों को ट्रैक कर सटीक हमला कर सकता है। इसका एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दुश्मन के रडार और मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है। विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, जो इसे ज्यादा दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। मार्क 1ए के रडार की रेंज और सटीकता पिछले संस्करण के मुकाबले कहीं बेहतर है। दुश्मन के विमानों का जल्दी पता लगाने के लिए इसमें अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगाया गया है। इनमें नया एवियोनिक सूट, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम जैसी तकनीक शामिल हैं। विमान के कॉकपिट में भी कई बदलाव हुए हैं।

स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, डिजिटल मैप जनरेटर और एडवांस रेडियो अल्टीमीटर जोड़े गए हैं। तेजस अधिकतम 1980 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 1,850 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। इसमें 8 अलग-अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में इसमें एंटी-शिप मिसाइल लगी हुई है। भविष्य में इसमें और आधुनिक मिसाइलें लगाने की तैयारी है। कहा जाता है कि तेजस अपने छोटे आकार के कारण रडार सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत भी रखता है।

दो दिन की पिकनिक, करोड़ों का खर्चा, कुछ नही हुयी चर्चा

भराड़ीसैंण। कुछ फिल्मों का क्लाइमेक्स आम जनता को पहले ही पता होता है । उत्तराखण्ड विधानसभा के सत्र का क्या अंजाम होगा। यह भी जनता पहले ही सुना देती है। आखिर 25 साल से यही ट्रेलर जो देख रहे हैं। 19 और 20 अगस्त को भराड़ीसैंण के विधानभवन में सिर्फ दो घण्टे चालीस मिनट तक चले विधानसभा सत्र में विपक्ष अपने मुद्दों पर चिल्लाता रहा। और सत्ता पक्ष का काम आसान हो गया। 22 अगस्त तक चलने वाला विधानसभा सत्र 20 अगस्त की दोपहर में ही समाप्त हो गया। विपक्ष पहले दिन से ही आपदा व कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग करता रहा। वेल में विपक्ष ने कागज फाड़े। माइक हिलाए। वोट चोरी समेत तानाशाह सरकार के जोर जोर से नारे लगाए। यही नहीं, पहले दिन चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने विधानभवन के मंडप के अंदर ही गद्दे, रजाई डालकर ऐतिहासिक रात बिताई। इस सत्र का सबसे गम्भीर पहलू यह रहा कि कांग्रेस के तात्कालिक व मौजूं सवाल (आपदा व कानून व्यवस्था) पर स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी टस से मस नहीं हुई। धराली-हर्षिल की जानलेवा आपदा पूरे देश ने देखी। और नैनीताल का अपहरण कांड व बेतालघाट की फायरिंग भी पूरे देश की नजरों में आई। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सख्त लहजा भी सुर्खियों में रहा। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि नियम 310 के तहत स्पीकर कम से कम गम्भीर आपदा पर चर्चा की मांग स्वीकार करेंगी। आपदा पर बहस होने पर कई पीढ़ितों से जुड़े अनछुए पहलू सामने आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मात्र डेढ़ दिन के गैरसैंण सत्र को लेकर यह भी सवाल उठ रहे है कि इससे अच्छा तो दून में ही कर लेते। इतने भारी खर्चे पर पूरी सरकारी मशीनरी को गैरसैंण क्यों ले जाया गया। बहरहाल, डेढ़ दिनी सत्र के पहले दिन 1 घन्टा 45 मिनट और दूसरे दिन 20 अगस्त को 55 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। इन डेढ़ दिन में कई बार सदन स्थगित हुआ। कुल 2 घण्टे चालीस मिनट सदन चला। कोई प्रश्नकाल नहीं। कोई सवाल जवाब नहीं। शोरगुल के बीच नये संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल की भी परीक्षा नहीं हो पाई। इस गतिरोध का लाभ उठाते हुए पूर्व की तरह इस बार भी सत्ता पक्ष ने हो हल्ले के बीच पांच हजार करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट और नौ विधेयक पास करवा लिए। नारेबाजी के बीच अन्य बिजनेस भी फ़टाफ़ट निपटा लिए गए। भराड़ीसैंण के अति लघु विधानसभा सत्र के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया में भाजपा-कांग्रेस के बीच मैच फिक्स की संभावना भी खुल कर जताई जा रही है। सत्र की समाप्ति के बाद हवाई व सड़क मार्ग से बचते बचाते अपने अपने ठौर पर लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन वही पुराने सवाल एक बार फिर पहाड़ी मोड़ पर अटके हुए हैं। बीते 25 साल में प्रदेश के बजट का आकार 25 गुना बढ़ चुका है। माननीयों के वेतन-भत्ते व सुविधाओं का दायरा भी फैलता जा रहा है। इन 25 सालों में कुछ अगर सिकुड़ा है तो वो विधानसभा के अंदर बहस व चर्चा का दायरा।

सदन के प्रमुख फैसले

5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित

पारित विधेयकों की सूची

उत्तराखंड विनियोग विधेयक, 2025

उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि-विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2025 झ जिसे आमतौर पर अंटी-रूपांतरण बिल कहा जा सकता है।

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक, 2025

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 झ

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 झ

उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025

अनुपूरक बजट 2025-26 के मुख्य बिन्दु

अनुपूरक बजट 2025-26 का आकार लगभग रू0 5315.39 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 2152.37 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग रू0 3163.02 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 1689.13 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 215.00 करोड़का प्रावधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।

महत्वपूर्ण प्रावधानः—

आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धसांव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 263.94 करोड़ तथा जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु रू0 13.00 करोड़

आगामी कुम्भ मेला 2027 के दृष्टिगत वृहत् निर्माण कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़

पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु रू0 188.55 करोड़

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चालू कार्य हेतु रू0 90.00 करोड़

पेयजल विभाग के अन्तर्गत के०एफ०डब्ल्यू परियोजना हेतु रू0 90.00 करोड़

अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (90% के०पो०) हेतु रू0 48.00 करोड़

ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु रू0 50.00 करोड़

हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु रू0 50.00 करोड़

पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0 60.00 करोड

मानसखंड माला मिशन (अवस्थापना सुविधा) हेतु रू0 15.00 करोड़

विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़

रिस्पना बिन्दाल की एलिवेटेड रोड़ हेतु भूमि ऋण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु रू0 925.00 करोड़

नन्दा देवी राजजात यात्रा हेतु निर्माण कार्य हेतु रू0 40.00 करोड़

पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 25.00 करोड़

राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम हेतु रू0 23.66 करोड़

हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण योजना हेतु रू0 05.00 करोड़

अस्पताल के निकट तीमारदारों हेतु विश्राम गृहों के निर्माण हेतु रू0 05.00 करोड़

विद्युत टैरिफ सब्सिडी हेतु रू0 125.00 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना 80% (के0पो०) हेतु लगभग रू0 114.17 करोड़

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी०एम०-अभीम) के अन्तर्गत रू0 25.55 करोड़

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 एवं फेज 2 के लंबित कार्य हेतु रू0 40. 00 करोड़

मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सामर्थ्य के अन्तर्गत रू0 15 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 90%(के0पो०) हेतु रू0 95.25 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रू0 10.00 करोड़

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु रू0 10.00 करोड

मिलेट मिशन हेतु रू0 08.00 करोड़

सूचना विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन तथा अधिष्ठान हेतु रू0 120.00 करोड़

अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु रू0 78.89 करोड़

प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 75.00 करोड़

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़

शारदा रिवर फ्रंट योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 50.00 करोड़

महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण हेतु रू0 50.00 करोड़

पर्म्पिंग आधारित योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु रू0 25.00 करोड

आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु रू0 13.00 करोड़

दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु रू0 05.00 करोड़

जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान हेतु रू0 20.00 करोड़

विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री / निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रू0 20.00 करोड़

टाटा टेक्नोलॉजी माडल हेतु रू0 20.00 करोड़

राष्ट्रीय प्रतियोगताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु रू0 18.00 करोड़

प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन के अन्तर्गत हेतु रू0 6.00 करोड़

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना हेतु रू0 10.00 करोड

पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 10 करोड

परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु रू0 3.1 करोड

राजस्व उप निरी०/राज०निरी० को शासकीय कार्य हेतु लैपटॉप / इंटरनैट उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 5.00 करोड

दुधारू पशुओं को साईलेज उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 10 करोड

गौ सदन का निमार्ण हेतु रू0 5.00 करोड

परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड हेतु रू0 5.00 करोड

संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण हेतु रू0 3.00 करोड

शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 2.86 करोड़

उत्तराखण्ड शहीद कोष हेतु रू0 2.50 करोड़

सम्पादकीय

विपक्ष की भूमिका पर सवाल

गैरसैंण में विधानसभा सत्र की नियति एक बार फिर वही देखने को मिली है जो अक्सर यहां होने वाले सत्र में नजर आती है। इस बार भी यहां विपक्ष के हंगामे के कारण मात्र डेढ़ दिन ही सत्र चल पाया लेकिन इसी में सरकार ने बेहद तेजी दिखाते हुए नौ जरूरी विधायक पास करने में सफलता हासिल की। यह विधानसभा सत्र इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब सरकार की नीतियों के विरोध में विपक्ष ने सदन में ही अपना बोरिया बिस्तर बिछाया और रात गुजारी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए अपील भी की लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आया। सदन के दूसरे दिन भी सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया इसके बाद यह महत्वपूर्ण सत्र समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। विपक्ष आपदा समेत पंचायत चुनाव में सदस्यों के अपहरण को लेकर मुखर था और इन्हीं खास मुद्दों को लेकर पहले दिन से शुरू हुआ प्रतिरोध बढ़ता ही चला गया। विपक्ष के इस रवैये से आम जनता भी हतप्रभ है क्योंकि गैरसैण में सत्र आयोजित करना बेहद महंगा कार्य है और यदि सत्र सुचारू रूप से नहीं चलता है तो यह सीधे—सीधे समय और धन दोनों की बर्बादी ही दर्शाता है। विधानसभा में सभी नौ विधेयक पारित करने के साथ साथ 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया गया। इस बार के सदन की खास बात उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पास करना था, जिसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण गठित होने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलना अब तय है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। नए प्रावधानों के तहत गलत तरीके से लिव—इन—रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा बढ़ा दी गई है। सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून भी पास किया गया। अब जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा। विधानसभा का कोई भी सत्र राज्य के विकास और नई योजनाओं के लिए खास माना जाता है क्योंकि सत्र के माध्यम से ही समाज की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने का खाका तैयार होता है। विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो हंगामा के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा से छूट जाते हैं। गैरसैण में आयोजित होने वाले मानसून सत्र से पहले ही यह निश्चित लगने लगा था कि सत्र में हंगामा होगा और यदि मानसून सत्र अपनी निश्चित अवधि पूरी करता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका को लेकर आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जहां सरकार विपक्ष के रवैए को लेकर जनता के बीच अपना पक्ष रखेगी तो वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों को गलत साबित करने के लिए जनता के हित की बात करेगा। फैसला तो प्रदेश की जनता ही करेगी की क्या सदन को इस प्रकार से बाधित किया जाना चाहिए था या फिर जो कुछ विपक्ष ने सत्र के दौरान किया वह सही था?

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च—व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95 मामले केवल पाँच राज्यों—ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र—में केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक उप—स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे नि:शुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

जगत प्रकाश नड्डा

भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारी के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ—साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल सिकल सेल के आनुवांशिक संचरण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और स्वास्थ्य को भी बहाल करना है।

सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे—धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आदिवासी जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स (2021) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिकल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकट से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ज़ोर इसी के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023 में एनएससीईएम की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025—2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जाँच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या—आधारित आनुवंशिक जाँच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक एससीडी के आनुवंशिक संचरण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है।

पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च—व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95त्न मामले केवल पाँच राज्यों—ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र—में केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आदिवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निकट के एक उप—स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोगों के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

स्क्रीनिंग प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित पॉइंट—ऑफ—केयर डायग्नोस्टिक उपकरणों को लगाया गया है। शुरुआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति किट लागत ?100 से घटकर ?28 हो गई है। इस पहल ने एससीडी के लिए लागत—प्रभावी और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएँ सुनिश्चित की हैं।

इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; यह एससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुँच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रॉक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप—स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होती है।

यह मिशन सिकल सेल रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीतियों के रूप में आनुवंशिक परामर्श और जन जागरूकता पर भी ज़ोर देता है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्टेटस कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त हुई है। ये कार्ड परामर्श और उचित निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम बन गए हैं, जो परिवारों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद करते हैं जिनसे आनुवंशिक संचरण का जोखिम कम हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर, पंद्रह स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये संस्थान प्रसवपूर्व निदान और गंभीर सिकल सेल रोग जटिलताओं के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जोखिम वाले परिवारों को विशेष परिचर्या सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सिकल सेल रोग प्रबंधन की जटिलताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए गए हैं।

मिशन की सफलता संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। यह अंतर—मंत्रालयी समन्वय जनजातीय स्वास्थ्य के सामाजिक—सांस्कृतिक और भौगोलिक आयामों का समाधान करते हुए समग्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित अनुसंधान—आधारित गतिविधियों ने इस मिशन की लागत—प्रभावशीलता और रोगी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

हालांकि इस मिशन की अब तक की उपलब्धियाँ बेहद सराहनीय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अब मिशन की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। अब मिशन का तात्कालिक ध्यान आनुवंशिक परामर्श, जन जागरूकता अभियानों और आनुवंशिक स्टेटस कार्डों के वितरण के विस्तार पर होगा। सामुदायिक स्तर के मंचों का प्रभावी उपयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा कि प्रत्येक वाहक और रोगग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या और सहायता प्राप्त हो। उन्नत अनुसंधान प्रयास मिशन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

इस मिशन की असली भावना इसके आदर्श हमारे संघर्षकर्ताओं को साथ, हमारे उत्तरजीवियों को संबल, और हमारे योद्धाओं को समर्थन में निहित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक नवाचार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के संयोजन से भारत सिकल सेल एनीमिया को समाप्तस करने और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पंर है।

जैसे—जैसे भारत वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग उन्मूलन के अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन इसमें आशा की किरण बनकर उभरा है। यह इस बात का द्योतक है कि जब सरकार, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और समुदाय समान हित के लिए एकजुट होते हैं, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को इस रोग के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा को न सहना पड़े।

सिकल सेल एनीमिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई सिर्फ़ एक आनुवंशिक रोग से लड़ने तक सीमित नहीं है—यह हाशिए पर रहने वाले हमारे देश के समूहों के लिए समानता, सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता है। मीना जैसी महिलाओं के अनुभवी मार्गदर्शन में, यह मिशन लक्षित स्वास्थ्य सेवा पहलों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, जो जनजातीय स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आइए, इस अभूतपूर्व प्रयास का जश्न मनाएं और एक स्वस्थ, अधिक समावेशी भारत के निर्माण के अपने संकल्प को दोहराएं।

असल में महंगाई घट रही है?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर बढ़ रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से ताजा राहत अल्पकालिक साबित हो सकती है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के कारण अनेक कारोबार पर तलवार लटक रही है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार जाने का अंदेशा है। वैसी स्थिति में आम आमदनी में और गिरावट आएगी।

मुद्रास्फीति दर का घटना तब मांग को प्रोत्साहित करता है, जब आम आमदनी भी बढ़े। ऐसा होने का संकेत नहीं है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर बढ़ रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से ताजा राहत अल्पकालिक साबित हो सकती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई में आठ साल के सबसे निचले स्तर– यानी 1.55 प्रतिशत रही। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर को अलग कर दें, तो कोर यानी मुख्य मुद्रास्फीति दर 4.1 फीसदी रही, जो जून में 4.4 प्रतिशत थी। यानी कुल मिलाकर महंगाई बढ़ने की दर में गिरावट का ट्रेंड है। बहरहाल, इससे यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि असल में महंगाई घट रही है। ताजा सरकारी आंकड़े सिर्फ यह कहते हैं कि महंगाई अब पहले की तुलना में कम तेजी से बढ़ रही है। महंगाई दर जुलाई 2024 में जिस स्तर पर थी, अब उससे 1.55 प्रतिशत ऊपर है, लेकिन चूंकि पहले महंगाई इससे काफी अधिक तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए इस दर में आई गिरावट को राहत की खबर समझा गया है।बहरहाल, असल सवाल यह है कि क्या इससे आम उपभोग में बढ़ोतरी होगी, ताकि बाजार में मांग बढ़े? इसकी संभावना कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति दर कम रहना तब मांग को प्रोत्साहित करता है, जब आम आमदनी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक बढ़े। ऐसा होने का संकेत नहीं है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर बढ़ रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से ताजा राहत अल्पकालिक साबित हो सकती है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के कारण अनेक कारोबार पर तलवार लटक रही है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार जाने का अंदेशा है। वैसी स्थिति में आम आमदनी में और गिरावट आएगी।

गौरतलब है, उपभोग और मांग का ना बढ़ना हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या रही है। केंद्र ने इसका समाधान निकालने की जरूरत को नजरअंदाज किया है। जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के सस्ते आयात का लाभ आम उपभोक्ताओं को देकर तथा जीएसटी दरों में अनुकूल संशोधन कर वह ऐसा करने की स्थिति में है। फिलहाल, सरकार चाहे तो ऐसे कदम उठा कर मुद्रास्फीति दर में गिरावट से बनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठा सकती है। खाने—पीने की चीजों की महंगाई नियंत्रित रहे और सरकार की पहल से लोगों की जेब में पैसा बचे, तो उस स्थिति में वे अवश्य ही अधिक उपभोग के लिए प्रेरित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी।

अमेरिका से बिगड़ते संबंध

आवश्यक है कि विदेश नीति में किसी परिवर्तन से पहले उसके सभी आयामों पर गंभीरता से विचार हो। सिर्फ अमेरिका को सख्ती का संकेत देने के लिए अथवा जज्बाती प्रतिक्रिया में ऐसा करना भारत के हित में नहीं होगा।

अमेरिका से बिगड़ते संबंधों के साथ भारत में अचानक चीन से रिश्ते सुधारने और रूस से संबंध और गहरा करने की जरूरत पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। संकेत हैं कि भारत सरकार ने इससे संबंधित प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। उधर, ऐसा लगता है कि चीन ने इस नई परिस्थिति में अपने लिए अवसर देखा है। भारत और अमेरिका के बीच दरार चौड़ी हो जाए, तो चीन के लिए यह अच्छी स्थिति होगी। यह अमेरिका की चीन को घेरने की रणनीति के लिए एक झटका होगा, जिसे स्वरूप देने में गुजरे डेढ़ दशक में अमेरिका ने अपनी काफी ऊर्जा लगाई है। तो खबर है कि चीन ने भारत को उर्वरकों के निर्यात रोकने की नीति में ढिलाई दे दी है और कथित रबर डंपिंग के मामले में भारत के खिलाफ जांच रोक दी है। इधर भारत ने दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का ठोस संकेत दिया है। इसी बीच खबर आई है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे। वांग सीमा विवाद पर वार्ता के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। नई दिल्ली में भारत के विशेष प्रतिनिधि अजित डोवल से उनकी बातचीत होगी। साथ ही एलान हुआ है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 21 अगस्त को मास्को जाएंगे। ये तमाम कूटनीतिक गतिविधियां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तय चीन यात्रा से पहले हो रही हैं। रूस और चीन दोनों भारत के साथ अपनी त्रिपक्षीय वार्ता का क्रम फिर शुरू करने पर जोर दे रहे हैं।

राजामौली ने लॉन्च किया राव बहादुर का टीजर

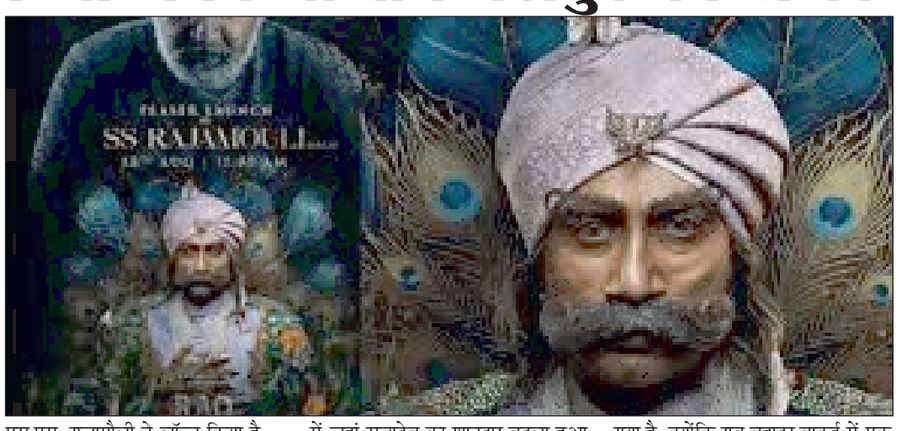

सबसे बड़ा दुश्मन है शक और महेश बाबू प्रेजेंट्स वेंकटेश की राव बहादुर के टीजर में दिखाया गया है कि कहानी का हीरो इसी दुश्मन यानी शक के वश में है. इस फिल्म को जीएमबी एंटरटेनमेंट, ए+एस मूवीज, श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स और महायान मोशन पिक्चर्स ने बनाया है.

महेश बाबू प्रेज़ेंट्स, वेंकटेश महा की फिल्म राव बहादुर का फर्स्ट लुक पोस्टर आते ही छा गया था. इसमें सत्यदेव का जबरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. पोस्टर ने साफ कर दिया था कि कुछ अलग और खास आने वाला है. जैसे—जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, मेकर्स ने रिलीज़ को लेकर सबको उत्सुक बनाए रखा और अब इंतजार खत्म हो चुका है. यूनिक और दिलचस्प अंदाज में बनी इस फिल्म का धमाकेदार टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि राव बहादुर के टीजर को खुद एस.एस. राजामौली ने लॉन्च किया है.

राव बहादुर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा टीजर अब रिलीज हो गया है. इसमें सत्यदेव नजर आ रहे हैं और यह टीजर पैन—इंडिया फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. पहले लुक में जहां सत्यदेव का शानदार बदला हुआ अंदाज दिखा था, वहीं टीजर हमें एक बड़ी और अलग दुनिया में ले जाता है. ये टीजर अपने अनोखे स्टाइल और शानदार विजुअल्स से सबको आकर्षित कर रहा है. अब दर्शकों का जोश और भी बढ़ गया है, क्योंकि राव बहादुर वाकई में एक अलग और जबरदस्त पैन—इंडिया फिल्म बनने वाली है.राव बहादुर का टीजर हमें एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, जहां सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां छिपी हुई हैं.

यूएस ओपन 2025 : विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने मिक्स डबल इवेंट से नाम लिया वापस

नईदिल्ली, विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2025 के मिश्रित युगल स्पर्धा से अपना नाम वापस ले लिया है. हाल ही में कालीस अल्काराज के खिलाफ सिनसिनाटी ओपन का फाइनल मैच भी वो पूरा नहीं खेल सके थे और चोट के कारण आगे मैच खेलने से मना कर दिया था. जिसके कारण स्पेनिश खिलाड़ी अल्काराज पहली बार सिनसिनाटी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया. यूएस ओपन के मिश्रित युगल स्पर्धा में सिनर को चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा के साथ भाग लेना था. हालाँकि, आयोजकों ने पुष्टि की है कि यह जोड़ी साल के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम में भाग नहीं लेगी. उनकी जगह डेनियल कॉलिन्स और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी को शामिल किया गया है. यह घोषणा मंगलवार को होने वाले पहले मैच से कुछ घंटे पहले की गई.

सिनर का अल्काराज के साथ सिनसिनाटी ओपन फाइनल सिर्फ पांच गेम तक चला क्योंकि सिनर शुरू से ही अस्वस्थ दिखाई दिए और चिकित्सा उपचार के बावजूद पहले सेट में 0—5 से पिछड़ने के बाद बाकी सेट नहीं खेल पाए. सिनर ने यूएस ओपन को देखते हुए फाइनल मैच में आगे खेलने से पीछे हट गए.

एशिया कप के टी—20 प्रारूप में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली है सबसे बड़ी पारियां

नईदिल्ली,एशिया कप के टी—20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। कभी तूफानी अंदाज में चौकों—छक्कों की बरसात हुई तो कभी दबाव भरे मौकों पर धैर्य और कौशल का कमाल देखने को मिला।

इन पारियों ने न सिर्फ मैच का रुख बदला, बल्कि टूर्नामेंट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गईं। आइए इस टूर्नामेंट के आगामी संस्करण से पहले भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं। एशिया कप के टी—20 प्रारूप में भारत के लिए एकमात्र शतकीय पारी विराट कोहली ने खेली है। उन्होंने साल 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ 122* रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 61 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। भारतीय टीम के 212/2 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 111/8 का स्कोर ही बना पाई थी।

रोहित शर्मा सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मीरपुर में 83 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 55 गेंदों का सामना करते हुए ये धमाकेदार पारी खेली थी। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.90 की रही थी। रोहित की पारी की मदद से भारत ने पहली पारी में 166/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश 121/7 का स्कोर ही बना पाई थी। इस सूची में तीसरे स्थान पर भी रोहित ही हैं।

20 साल के करियर में बनी मैं हर किरदार की मास्टर: रेजिना कैसेंड्रा

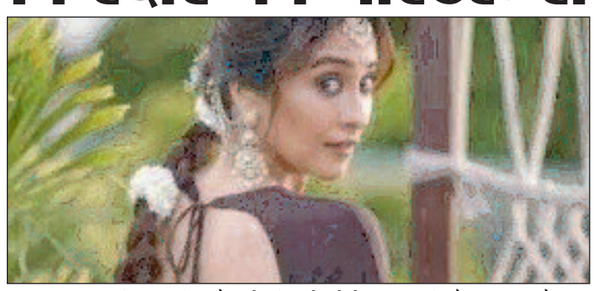

जाट, साकिनी—डाकिनी और केसरी चैप्टर—2 में अभिनय करने वाली रेजिना कैसेंड्रा ने इंडस्ट्री में गुजारे 20 साल को बेहतरीन बताया है। उनके मुताबिक सफर देखने में जितना हसीन है, दरअसल, वैसा था नहीं। इसी साल उनकी दो बड़ी फिल्में केसरी—चैप्टर टू और जाट, रिलीज हुईं। दोनों ही किरदार एक दूजे से एकदम जुदा। एक्ट्रेस के अंदाज को इंडस्ट्री के नामदार पसंद करने लगे हैं। अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें अलग—अलग भाषाओं में काम करने के खूबसूरत मौके मिले। बोलीं, मेरा सिने सफर काफी शानदार रहा है। मुझे अलग—अलग भाषाओं में काम करने के मौके मिले हैं, इसके लिए मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं। अब, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन मेरे लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कई बार मुझे खुद पर शक होता था कि मैं खुद को और दूसरों की उम्मीदों पर खरी भी उतर पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मेरे लिए चीजें बिल्कुल अलग थीं।

रजनीकांत की कुली का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 200 करोड़ रुपये से चंद कदम दूर

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को 14 अगस्त को ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि, कुली कमाई के मामले में वॉर 2 से आगे है। बॉक्स ऑफिस पर कुली का कारोबार तेजी से 200 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रहा है। आइए जानें फिल्म ने चौथे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, कुली ने अपनी रिलीज के चौथे यानी रविवार को 35 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 194.25 करोड़ रुपये हो गया है।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी

नईदिल्ली,एशिया कप का अगला संस्करण टी—20 प्रारूप में 9 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी संस्करण के लिए भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इस बीच टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी पर एक नजर डालते हैं। भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। भारतीय टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, और जितेश शर्मा प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और जायसवाल को स्टैंडबाई खिलाड़ियों के तौर पर चुना गया है।भारतीय टीम ग्रुप—ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ मौजूद है। सूर्यकुमार के नेतृत्व वाली टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को भारतीय टीम के सामने सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम होगी। आखिर में 19 सितंबर को ओमान के विरुद्ध भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष—2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी। अब तक 2 एशिया कप टी—20 प्रारूप में खेले गए हैं, जिसमें से 1 में भारतीय टीम विजेता बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2016 में खेले एशिया कप को भारत ने जीता था। खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। इसके बाद 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए भारतीय टीम सुपर—4 चरण से भी आगे नहीं बढ़ सकी थी।

वर्षाकाल में आमसौड़ के ग्रामीणों को सता रहा भूस्खलन का खतरा

आमसौड़ गांव जो इन दिनों भूस्खल की जद में है।

लगातार शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम ने नहीं दिया ट्रीटमेंट पर ध्यान

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : वर्षाकाल में दुगड्डा विकासखंड के ग्राम आमसौड़ के ग्रामीणों को पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा सता रहा है। बारिश होने पर ग्रामीणों की आंखों से नींद गायब हो जाती है। ऐसे में कई परिवार अन्यत्र शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम ने ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं दिया। बताते चलें कि वर्ष 2023 के सितंबर माह में अतिवर्षा के चलते आमसौड़ गांव के ऊपर केलापानी का पहाड़ दरकने लगा व मलबा व बोल्डर गांव की ओर आ गए। प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि सरकारी तंत्र उन्हें भूस्खलन के दंश से निजात दिलाएगा। लेकिन, वर्ष भर सरकारी सिस्टम ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली। उधर, भूस्खलन जोन पर ट्रीटमेंट कार्य नहीं हुए। इस बीच बीते वर्ष छह जुलाई को भी पहाड़ी का हिस्सा दरकते हुए भारी मलबे व बोल्डर के साथ गांव के ऊपर गिर गया, जिससे पहाड़ी के नीचे कई भवनों के कमरों में मलबा भर गया था। साथ ही गांव के लिए बिछाई गई पेयजल लाइन भी टूट गई थी। इसके बाद बीते वर्ष 22 अगस्त की मध्य रात्रि अतिवृष्टि के दौरान पहाड़ी फिर दरक गई और भारी मलबा व बोल्डर गांव के ऊपर आ गए। भारी मलबे की चपेट में आने से जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित सीएचसी सेंटर व एक दुकान की दीवार ढह गई थी। वहीं, कई घरों में भारी मलबा भी आ गया था। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में अपने घरों को छोड़कर पंचायत भवन में शरण ली। सुरक्षा को देखते हुए गांव में पहाड़ी के नीचे रहने वाले 25 परिवारों में से दस परिवार कोटद्वार व दुगड्डा में किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए।

आज तक नहीं ली गई सुध

प्रशासन ने आमसौड़ गांव में भू-स्खलन रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। हालात यह है कि अभी तक गांव का भूगर्भीय सर्वे तक नहीं हुआ। नतीजा, आपदा प्रभावित होने के बावजूद गांव को आपदाग्रस्त गांवों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान पहाड़ी से नाले के रूप में पूरा पानी गांव की ओर आया। इस नाले में जमा मलबे की अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। ऐसे में इस वर्षा काल में भी ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है।

सैनिक के साथ हुई मारपीट से पूर्व सैनिकों में रोष

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोल प्लाजा में सेवारत सैनिक पर जानलेवा हमले की घटना से पूर्व सैनिकों में गहरा रोष है। पूर्व सैनिकों ने घटना की निंदा करते हुए टोल प्लाजा संचालक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की मांग की है।

सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर केशर सिंह बिष्ट ने कहा कि 17 अगस्त को मेरठ के टोल प्लाजा में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना से पूर्व सैनिकों में गहरा रोष है। कहा कि पहचान पत्र दिखाने व फ्लाइट के कागजात दिखाने के बाद भी यह घटना घटी है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कहा कि एनएचएआई की ओर से टोल प्लाजा संचालक पर लगाया गया 20 लाख का जुर्माना काफी कम है।

उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले का संज्ञान लेकर आरोपियों को तीन माह के भीतर कठोर सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने टोल प्लाजा के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एक करोड़ का जुर्माना लगाने और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की मांग भी की है।

दुगड्डा में बीस सितंबर से होगा रामलीला का मंचन

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : प्रखंड दुगड्डा में रामलीला कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 सितंबर से रामलीला मंचन करने का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम विगत वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे को सार्वजनिक किया गया, तत्पश्चात रामलीला मंचन के लिए कार्यकारिणी का गठन करते हुए प्रदीप बडोला को अध्यक्ष व राहुल जैन को महासचिव बनाया गया। अन्य पदों में विनायक नेगी, सौरभ गुप्ता, बृजमोहन रावत, वीरेंद्र शाह को उपाध्यक्ष बनाया गया। दीपक ध्यानी को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। योगेंद्र बिष्ट को व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी गई। वीरेंद्र सिंह नेगी, जयेंद्र सिंह सहव्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। संजीव कपूर, विपिन गर्ग, संजीव कोटनाला, आशीष राजपूत को निर्देशक बनाया गया है। धर्मेंद्र गोयल, संदीप नेगी, नरेंद्र शहनाई, गिरीश गौड, वीरेंद्र शाह को संरक्षक मंडल का सदस्य बनाया गया है। नरेंद्र शहनाई, जयेंद्र सिंह को संगीत निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई। अनूप गुप्ता, अभिमन्यु, मनोज भट्ट, सर्वेंद्र मनराल, आशीष, करन, आयुष, हैप्पी, देवदत्त, दिव्यांशु, उमंग, अंकित, अर्जुन सिंह को सह व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी गई। रामलीला मंचन कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप बडोला ने कहा कि रामलीला मंचन का रिहर्सल 25 अगस्त से शुरू किया जाएगा तथा रामलीला का मंचन 20 सितंबर से किया जाएगा।

पति के नशे की लत से परेशान महिला ने छोड़ा घर

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : अपने पति के नशे की लत व मारपीट से परेशान होकर एक महिला ने अपने बेटे के साथ घर छोड़ दिया। बुधवार को पुलिस ने महिला व उसके बेटे को गुजरात के अहमदाबाद से सकुशल बरामद किया है।कुछ दिन पूर्व मामले में मुकेश नामक एक व्यक्ति की ओर से कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी व बच्चा घर से लापता हो गया है। काफी खोजबीन करने के बाद भी दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर्वलांस व अन्य सूत्रों से पुलिस ने महिला को अहमदाबाद से बरामद किया। महिला ने बताया कि उनका कुछ वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। लेकिन, उसका पति आए दिन नशे में उसके साथ मारपीट करता है। बताया कि इससे परेशान होकर वह अपने बेटे के साथ घर से चली गई थी। महिला ने अपने पति के साथ रहने से इंकार किया। कहा कि वह उससे अलग स्वयं ही बेटे का पालन-पोषण करना चाहती है।

कार्यालय- नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल

ई-मेल - eonpthalisain@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

20 अगस्त 2025 ई0

पत्रांक संख्या-172/से0प्र0प्रो0/उपविधि/प्रकाशन/न0प0थली0/2025-26/- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी, गढ़वाल सीमांतर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड- (ज) (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 की उपधारा-1 (ii), (iii) अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2025 बनाई जाती है जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 (1) के अंतर्गत दी गई शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन करने हेतु नगर पंचायत थलीसैंण की बोर्ड बैठक दिनाँक 12.08.2025 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रोटोकॉल फॉर सेप्टेज मैनेजमैन्ट 2025 बनाये जाने की स्वीकृति के उपरानत यह विज्ञप्ति आपत्ति एवं सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिससे नागरिकों पर प्रभाव पड़ने जा रहा है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियन्त्रण व विनियमन करने हेतु प्रॉटोकोल फॉर सेप्टेज मैनेजमैन्ट 2025 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग, विभाग आदि की कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत थलीसैंण में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1
सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2025 कहलाएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल के सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशित होने से प्रभावी होंगे।

2- ये उप-नियम नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल की सीमाओ के भीतर लागू होंगे।

1- प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है की एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलो में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेप्टीक टेंट, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1- राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ''राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति'' वर्ष 2017 घोषित की है जिसमें शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओ का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई हो सके।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉलः

नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी में ''उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाएगी जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया है ताकि इसका अनुपाल शहरों/नगरों में हो सके आदेश से 597/

4 (2)-यू0डी0-2017-50/16, दि0 22.05.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल पौड़ी शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके इस प्रोटोकल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेण्ट सेल का आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितीकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा0सं0 समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी के नियमित ढाँचा रिक्त करने एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत जो कि यहा स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उदेश्या एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उदेश्या एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः

1. निर्माण, से सेफ्टीक टैंक के दैनिक रख रखाव और शौचालय के गढ़े परिवहन इलाज और सुरक्षित रख रखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से संबन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़े से फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से संबन्धित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।
4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेफ्टीक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

* सेफ्टीक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना मैकेनिकल वेक्यूम टेन्कर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकल में वर्णित है को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्ट वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किए जाएंगे छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जाएगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेण्ट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक पंचायत थलीसैंण कि अपनी एक सैप्टिक इकाई होगी परन्तु इस निकाय में सैप्टिक इकाई न होने के कारण सैप्टिक को निकाय 160 कि0मी0 दूर अन्तर्गत स्थिति श्रीनगर के उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा या निकाय के निकट कोई अन्य एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा या डी0आर0एफ0 तकनीकी से ट्रीटमैन्ट किया जायेगा। भविष्य हेतु एक अलग सैप्टेज ट्रीटमैन्ट प्लान का निर्माण हेतु भी कार्ययोजना तैरू किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी संयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारण किया जाएगा फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रोन गलब्स, रबड़, बूट, चेहरे का मास्क और आंखो की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाएगा इसके लिए जागरूकता भी की जाएगी इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाएंगे जब सेफ्टीक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो धूम्रपान वर्जित रहेगा।
2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेफ्टीक टैंक में और शौचालय गढ़े में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-बाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा बच्चो को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाएगा एवं टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाए कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हौल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायो के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जो कि गाड़ियो के परिवहन हेतु होगा ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है ।

सारणी । पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंम्भिक पंजीकरण : रू0 2000.00 प्रति गाड़ी

ब. नवीनीकरण : रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7.उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गढ़े जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल सलज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है कि सेप्टेज टैंक के भरने, शौचालय के गढ़े परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से संबन्धित है उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा जो कि समय-समय पर इससे संबन्धित है ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किए जाए जो निम्नवत है।

7.5 उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से संबन्धित भवन/सेप्टेज टैंक पंचायत से यू0एल0बी0 में जमा किया जाएगा।

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जाएगी जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टेज टैंक और शौचालय के गढ़े से संबन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः-

पंचायत क्षेत्र मे सेप्टेज टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ़े या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टेज टैंक ओवर-प्लो तो नहीं हो रहा है तुरंत पंचायत से सुपरवाईजर को भेज कर जाँच करवाएँगे इसके अलावा पंचायत में सेप्टिक टैंको को खाली कराने के आवेदन के आने पर पंचायत द्वारा जाँच करायी जाएगी कि सेप्टेज टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे तसदीक होने पर निम्न शुल्क वसूला जाएगा।...

1:- पंचायत के सीवर टैंकर की क्षमता 4000 लीटर

2:- पालिका सीमा के बाहर
1- रू0 6000/- प्रति फेरा, तथा जल संस्थान एस0टी0पी0 प्रति फेरा शुल्क रू0.100/- अतिरिक्त रहेगा
2- दो फेरे होने पर शुल्क रू0 10000/- तथा जल संस्थान एस0टी0पी0 शुल्क रु 2000/- अतिरिक्त रहेगा ।
3- भवन स्वामी पालिका में शुल्क जमा कराएगा।
4- सेप्टिक टैंक में ज्यादा फिकल होने पर तीसरे फेरे की स्थिति होने के कारण संबन्धित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात टूट प्रदान की जाएगी।

4:- पालिका द्वारा यह भी देखा जाएगा कि यदि कोई सेप्टेज टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि संबन्धित सेप्टेज टैंक में 4000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नहीं भर पाएगा उपरोक्त निर्धारित दरों में आवश्यक टूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

5:- पंचायत द्वारा दी गयी उपर्युक्त दरे 2 साल तक वैध मानी जाएंगी। तद्पश्चात बोर्ड प्रस्ताव उपरांत नयी दरे सृजित की जाएंगी

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देनाः

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गढ़े या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मलनिस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जाएगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत थलीसैंण पौड़ी में जमा की जाएगी। तथा सैप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जाएगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टेज टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण मशीनरी परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतु प्रशिक्षण होगा।

9.दंड

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट/आर0एन0एन0 का रजिस्ट्रीकरण न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र.सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
01	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत
02	सेप्टेज/फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर करना	1000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	परमिट का निरस्तीकरण
03	पंजीकरण न करना/ पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु
04	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना एवं जी0पी0एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना

दीपक प्रताप
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत थलीसैंण

श्रीमती वीरा देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत थलीसैंण

(1181/73)

संक्षिप्त समाचार

संगठन ने धूमधाम से मनाया बटालियन का स्थापना दिवस

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : तृतीय गढ़वाल राइफल्स गौरव सेनानी संगठन की ओर से बटालियन का 110वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि देश की रक्षा में दिए गए वीर सैनिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

भाबर स्थित एक बारातघर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह व संरक्षक उम्मेद सिंह नेगी ने लोगों को गढ़वाल राइफल्स के इतिहास के बारे में बताया। कहा कि गढ़वाल राइफल्स की तीसरी बटालियन की स्थापना 20 अगस्त 1916 को लैंसडौन में हुई थी। बटालियन के प्रथम कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेएमटी हग के स्थापना से लेकर अब तक बटालियन के जवानों ने विभिन्न युद्धों और ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। बटालियन को भारत-पाक युद्ध के दौरान वर्ष 1948 में जम्मू कश्मीर में टीथवाल की लड़ाई में वीरता पदक मिले। इस मौके पर आलम सिंह, दलबीर सिंह रावत, अर्जुन सिंह, बलराम ध्यानी, मुर्खल्या सिंह बिष्ट, प्रेम सिंह, पृथ्वी पाल सिंह, जानकी बल्लभ, राजेंद्र सिंह, बृजमोहन सिंह, सोहन सिंह, अनिल सिंह, हिम्मत सिंह, सुदर्शन सिंह, नरेंद्र ध्यानी, कमल किशोर, दीवान सिंह, यशवंत सिंह, जसवंत जुयाल, दीपक सुयाल आदि मौजूद रहे।

जिले के 15 ब्लॉकों में लगेंगे शिविर

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए जिले में बैंक शाखावार ऋण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले के पन्द्रह ब्लॉकों में शिविर 20 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगें।

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों सहित ग्रामीणों को अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सृजित हो सकें। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं को रोस्टर के तहत शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए है। बताया कि कार्यक्रम के तहत 20 अगस्त से 9 सितंबर तक जिले के सभी 15 ब्लाकों में बैंक शाखा स्तर पर ऋण शिविर आयोजित होंगे। इसमें राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों की शाखाएं शामिल रहेंगी।

चार लोगों को मिला जसवंतगढ़ सम्मान रत्न

जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति की ओर से चलाई जा रही यात्रा का हुआ समापन

आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौजूद पूर्व सैनिक व अन्य लोग

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : धुमाकोट को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रही जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति की दूसरे चरण की यात्रा संपन्न हो गई है। इस दौरान सदस्यों ने सरकार से धुमाकोट को जसवंतगढ़ के नाम से जिला बनाने की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा के लिए चार लोगों को भी सम्मानित किया गया। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रामरतन नेगी के नेतृत्व में लंबे समय से यह यात्रा चल रही थी। मंगलवार को भारतीय सेना के साहसी व महावीर चक्र विजेता अमर बलिदानी जसवंत सिंह रावत के जन्मदिवस पर यात्रा का धुमाकोट में समापन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व ब्लाक प्रमुख बीरोंखाल राजेश कंडारी, पूर्व ब्लाक प्रमुख नैनीडांडा मधु बिष्ट, जंगबहादुर नेगी व रंजना रावत को समाज सेवा के लिए जसवंत रत्न सम्मान दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक आरपी ध्यानी ने कहा कि स्थानीय जनता लगातार धुमाकोट को जिला बनाने की मांग उठा रही है। समिति के अध्यक्ष राजदर्शन सिंह रावत ने कहा कि धुमाकोट सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में इसकी अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए धुमाकोट का अलग जिला बनना आवश्यक है। रामरतन नेगी ने कहा कि यात्रा के दूसरे चरण का समापन है। यात्रा के दौरान समिति को ग्रामीणों का अपार समर्थन मिला। कहा कि तीसरे चरण की यात्रा 14 नवंबर से शुरु होगी। इस मौके पर राजेश ध्यानी, जीएस नेगी, राम प्रसाद डोबरियाल आदि मौजूद रहे।

प्रतियोगिता में विवेक भंडारी रहा अव्वल

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : सद्भावना दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज सतपुली में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विवेक भंडारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते विद्यार्थी

बुधवार को विद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य देव सिंह ने विद्यार्थियों को सद्भावना दिवस के महत्व के बारे में बताया। कहा कि सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। राजीव गांधी हमारे देश के छठवें प्रधानमंत्री थे। यह दिवस समाज में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कहा कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर समाज की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को विद्यालय में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विवेक भंडारी ने प्रथम, तनुज दत्त ने द्वितीय एवं गीतांजली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक की भूमिका में सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज सतपुली के सहायक अध्यापक प्रीतम सिंह एवं मनमोहन सिंह नेगी थी। कार्यक्रम का संचालन ममता नेगी ने किया।

बुआखाल-रामनगर हाईवे पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू

जयन्त प्रतिनिधि।पौड़ी : नेशनल हाईवे बुआखाल-रामनगर पर पाबौ के कलगड़ी में टूटे मोटर पुल की जगह बुधवार को बैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बुधवार को एनएच लोनिवि धुमाकोट ने बैली ब्रिज पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी। छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू होने से काफी राहत मिल गई है। इससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। इस बैली ब्रिज का वर्चुवल शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधिवत शुरूआत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैली ब्रिज बनने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। बैली ब्रिज को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। बता दें कि यह मोटर पुल बीती 6 अगस्त को जिले में आई भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से टूटा था और तब से पाबौ से आगे हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी थी। एनएच के ईई अरुण कुमार के मुताबिक फिलहाल ब्रिज पर हल्के वाहन की अवाजाही शुरू की गई है। एक हफ्ते बाद इस पर भारी वाहन भी चल सकेंगे। इसके लिए अभी काम चल ही रहा है। इस बैली ब्रिज के बनने से लोगों को सुविधा हो गई है। आपदा में जब यह पुल टूटा तो जिले के आपदाग्रस्त गांव सैंजी बौर बुरांशी में भी रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाई थी। बाद में थलीसैंण तहसील से टीम बुरांशी गांव पहुंच सकी। वहीं बैली पुल के बनने से अब थलीसैंण से लेकर पैठाणी, चिपलघाट, त्रिपालीसैंण और आगे के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय का सफर तय करने में करीब 60 किलोमीटर की दूरी अधिक तय नहीं करनी पड़ेगी।

जिपंस की अनिभव पहल, स्कूली बच्चों के लिए लगाई नि:शुल्क बस

रुद्रप्रयाग : हाल ही में त्रियुगीनारायण जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य चुने गए अमित मैखंडी ने अभिवन पहल करते हुए करीब 35 स्कूली छात्र-छात्राओं को एक महीने तक निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई है। यह सभी बच्चे बडासू से फाटा स्कूल तक आने में 7 किमी. की दूरी पैदल तय करते थे। मैखंडी की इस पहल का समाज में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। केदारघाटी के मैखंडा गांव निवासी अमित मैखंडी निरंतर समाज सेवा करते रहे हैं। इस बार उन्होंने स्कूली बच्चों को सबसे बड़ी राहत दी है। अमित मैखंडी ने बताया कि बहुत समय से स्कूली बच्चों को पैदल जाते देखकर मन दुखी होता था। बरसात में रास्ते में स्लाइडिंग जोन हैं जहां पत्थर गिरते रहते हैं। बच्चे बारिश में भीगकर स्कूल पहुंचते हैं। सड़क मार्ग से 7 किमी. की दूरी तय करने के लिए उन्हें वाहन नही मिल पाते हैं इसलिए सुबह 5 बजे घर से निकलकर किसी तरह स्कूल पहुंचते हैं। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र के करीब 35 बच्चों को बस में निशुल्क एक महीने बरसाती सीजन में यह सुविधा दी है। हालांकि बाद में सरकार और प्रशासन से बच्चों को सुविधा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किया याद

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

मालवीय उद्यान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित किया।

कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था उन्हीं की देन रही है। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में सुचिता बनाए रखने के लिए दल-बदल कानून बनाया, महिला सम्मान व सशक्तिकरण के लिए पंचायती विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था सहित कई अहम कार्य किए। इस मौके पर रंजना रावत, बलवीर सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, प्रेम सिंह पयाल, लक्ष्मी चौहान, शीला भारती, सरिता बिष्ट, गोपाल गुसांई मौजूद रहे।

आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते कांग्रेसी

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड बोर्ड की कक्षा-10 की परीक्षा राजकीय इण्टर कालेज कोटद्वार से संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है, मेरा अनुक्रमांक संख्या 23056206 है। मेरी कक्षा-10 उत्तीर्ण की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र वास्तव में कहीं गुम हो गये हैं तथा तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिल पाये हैं।

वंश बिष्ट पुत्र गोकुल सिंह बिष्ट निवासी ग्राम लालपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
(1179/21)

अदालती सूचना

न्यायालय श्रीमान असिस्टेन्ट कलैक्टर प्रथम श्रेणी कोटद्वार
राजस्व वाद सं0 13 सन् 2025
श्री कैलाश चन्द्र बनाम
उत्तराखण्ड सरकार आदि
समन बनाम–

1– श्री महेशानन्द पुत्र लोकादत्त, 2–श्री चिन्तामणी पुत्र ठगराम, 3– बलराम पुत्र ईश्वरीदत्त, 4– कमला देवी पत्नी जमन सिंह, 5– महाराज सिंह पुत्र जमन सिंह, 6–आदित्यराम पुत्र रूद्रीदत्त, 7– ओमप्रकाश पुत्र सुरेशानन्द, 8– कैलाशचन्द पुत्र सुरेशानन्द, 9– शकुन्तला देवी पत्नी सुरेशानन्द, 10– सतेश्वरी पत्नी सुन्दरमण्डी, 11– वीर सिंह पुत्र सुद्धी सिंह, 12– धनराज सिंह पुत्र जय सिंह, 13– गणेशी देवी पत्नी जय सिंह, 14– रमेश सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह उर्फ योगम्बर सिंह, 15– गेदा सिंह पुत्र भगत सिंह, 16– वीर सिंह पुत्र सुदीप सिंह, 17– कान्ती देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह, 18– आरती देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र, 19– अभिनव आयु 15 वर्ष पुत्र प्रकाशचन्द्र द्वारा बलीमाता आरती देवी, 20– अखिल आयु 12 वर्ष पुत्र प्रकाशचन्द्र द्वारा बलीमाता आरती देवी, 21– विनोद कुमार पुत्र धनीराम 22– कपोत्री देवी पत्नी चण्डी प्रसाद, 23– मुकेश चन्द पुत्र स्व0 चण्डी प्रसाद, 24– विकास कुमार पुत्र स्व0 चण्डी प्रसाद, 25– शयन सिंह पुत्र दलबीर सिंह, 26– सुरेन्द्र सिंह पुत्र दलबीर सिंह, 27– लक्ष्मी देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण ग्राम उमरावपुर पटटी हल्दूखाता तहसील कोटद्वार जिला पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

-प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने मेरे न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 229 बी0 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0सु0अधि0 के अन्तर्गत पेश किया है। जिसमें आपकी उपस्थिति वांछनीय है। अतः आपको हुक्म होता है कि आप दिनांक 22/08/25 को बवक्त 10.00 बजे दिन मेरे न्यायालय असालतन या वकालतन न्यायालय उपस्थित होकर अपनी पैरवी करना सुनिश्चित करे अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में वाद में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/08/15 को जारी किया गया है।

आज्ञा से
असिस्टेन्ट कलैक्टर
प्रथम श्रेणी कोटद्वार
(1180/11)

व्यापारी के साथ ग्राहक को भी हॉलमार्किंग की जानकारी होनी जरूरी

रुद्रप्रयाग : भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा मुख्यालय में स्वर्णकार व्यापारियों के साथ ही प्रशासन के साथ जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कई जरूरी जानकारियां साझा की गई।

बताया गया कि व्यापारियों के साथ ही आम ग्राहकों को भी हॉलमार्क की जानकारी होनी चाहिए। जिससे हॉलमार्क की सामग्री को ले सके। गुलाबराय स्थित कस्तूरी इन होटल में आयोजित कार्यशाला में स्वर्णकार व्यापारियों को अवगत कराते हुए भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं और स्वर्णकार व्यवसायियों को आभूषणों की शुद्धता एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत, अति विशिष्ट अतिथि महावीर पंवार, विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकुर खन्ना, जिला महामंत्री चन्द्र मोहन सेमवाल मौजूद थे।

इस मौके पर बीआईएस देहरादून के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी ने हॉलमार्किंग की गतिविधियों पर विस्तार से जानाकरी दी। बताया कि अब चांदी के आभूषणों पर एचयूआईडी आधारित हॉलमार्किंग लागू है, जबकि सोने में 9 कैरेट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। संयुक्त निदेशक सचिन चौधरी ने स्वर्णकारों और व्यापारियों को कई जरूरी जानकारी दी। इस मौके पर स्वर्णकार यूनियन से रिंकू वर्मा, विपिन वर्मा, राकेश वर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद थे। वहीं जिला कलेक्ट्रेट सभागार में भी भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्यशाला आयोजित की जिसमें अधिकारियों एवं आमजन को बीआईएस मानकों, हॉलमार्किंग, गुणवत्ता प्रमाणन एवं प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की जानकारी दी गई।

इस मौके पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बीआईएस मानक जनहित में अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागीय कार्यकलापों में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में सेवा वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सके। इस मौके पर सभी अधिकारी मौजूद थे। (एजेंसी)

पेयजल किल्लत से निजात दिलाने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

सतपुली : नगर पंचायत सतपुली के उपभोक्ताओं ने पेयजल किल्लत से निजात दिलाने की मांग उठाई है। उपभोक्ताओं ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही पेयजल किल्लत से निजात दिलाने की मांग की। कहा कि बीते एक सप्ताह से पंचायत क्षेत्र में पानी की नियमित सप्लाई नही हो रही है। जल संस्थान के अफसर समस्या पर कोई ध्यान नही दे रहे है। बुधवार को उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं पीएलबी पुष्पेंद्र राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने कहा कि नगर पंचायत के तीन वार्डों में पेयजल किल्लत से परेशानियां हो रही हैं।

उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायत क्षेत्र में पेयजल समाधान करने के साथ ही संस्थान के कनिष्ठ अभियंता का स्थानांतरण करने की भी मांग उठाई। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह नेगी, विजय, विशाल, द्वारिका प्रसाद, चंद्रमोहन सिंह, अमित रावत मौजूद रहे।

डा. अरविंद दरमोड़ा और प्रेम बल्लभ नैथानी का किया सम्मान

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल विवि के समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग द्वारा समाज कार्य सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर गंगा आरती समिति के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ नैथानी एवं पर्वतीय शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डा. अरविंद दरमोड़ा को विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप विभागाध्यक्ष प्रो. जेपी भट्ट, प्रो. किरन डंगवाल एवं डा. किरन बाला ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह, पौधा एवं सूती माला भेंट की। कार्यक्रम के दौरान विभाग के छात्रों द्वारा तैयार किए गए पोस्टरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। बुधवार को बिड़ला परिसर स्थित समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्वतीय शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डा. अरविंद दरमोड़ा ने कहा कि हर व्यक्ति का ध्येय समाज के लिए समर्पण होना चाहिए। समाजकार्य विभाग ने पहले भी जनहित के कार्यों की श्रृंखला चलाई है, जिसे नई पीढ़ी के शिक्षक एवं छात्र आगे बढ़ाएं। गंगा आरती समिति के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ नैथानी ने कहा कि गौ वंश की रक्षा, गंगा की निर्मलता व पवित्रता बनाए रखने के साथ महिलाओं को अग्रणी पंक्ति में लाना पहला प्रयास होना चाहिए। विभाग की ओर से समाजकार्य क्षेत्र में नैथानी और डा. दरमोड़ा के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागाध्यक्ष प्रो. जेपी. भट्ट ने विभाग की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक की भांति समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करना आवश्यक है। वहीं प्रो. किरन डंगवाल ने प्रेम बल्लभ नैथानी को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजिका असिस्टेंट प्रोफेसर डा. रितु मिश्रा ने कहा कि विभाग भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करता रहेगा। इस मौके पर डा. हनुमंत वाघमारे, डा. नितिन बिष्ट, शोध छात्र राजेंद्र बिष्ट, अंकित उछोली, लूसी कुमारी, अतुल सती, नंदिनी सती, प्रीति, विद्या, रुखसार व विभाग के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। (एजेंसी)

डीएम ने लगाई फटकार

पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार का निरीक्षण किया। डीएम ने जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति नियमित बहाल करने के निर्देश दिए। किचन व वाशरूम में साफ-सफाई की कमी और अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार करने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम स्वाति एस भदौरिया ने स्कूल में व्यवस्थाओं को एक महीने के भीतर सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की सुविधा हेतु वाशिंग मशीन व बिजली की आपूर्ति के लिए इनवर्टर दिए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने उपजिलाधिकारी एकेश्वर श्रेष्ठ गुनसोला को स्कूल का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सामने आया कि साल 2022 से अभी तक स्कूल प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।

पहाड़ी शैली में बनेगा कवि चन्द्रकुंवर का स्मारक

रुद्रप्रयाग : हिमवंत कवि चन्द्रकुंवर बर्त्वाल की यादों को संरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है, जिससे काव्य और साहित्य क्षेत्र से जुड़े साहित्यकारों में खुशी है। प्रकृति के चितेरे कवि चन्द्रकुंवर की कर्मस्थली पंवालिया में 8 लाख की लागत से कवि का स्मारक बनेगा जो उनके यहां अंत तक रहने की यादें सदा याद दिलाता रहेगा।

पुरातत्व विभाग पौड़ी द्वारा जनपद के भीरी स्थित पंवालिया में पहाड़ी शैली में कवि का स्मारक भवन तैयार किया जाएगा। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के सापेक्ष जिला योजना में 8 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस धनराशि से अभी स्मारक और प्रतिमा की स्थापना होगी। कार्यदायी संस्था इस दिशा में जल्द टेंडर की प्रक्रिया करते हुए निर्माण शुरू करने की कार्यवाही कर रही है। बता दें कि 20 अगस्त 1919 में जनपद के मालकोटी गांव में भोपाल सिंह के घर जन्मे चन्द्र कुंवर की प्राथमिक शिक्षा उडमाड़ा गांव में हुई। जबकि उन्होंने मिडिल की शिक्षा नागनाथ पोखरी व हाईस्कूल की शिक्षा पौड़ी के मेसमोर स्कूल से ली। इससे आगे की पढ़ाई उन्होंने देहरादून और प्रयाग विवि लखनऊ में की। क्षय रोग से पीड़ित चंद्रकुवर के स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। शिक्षण कार्य के दौरान ही उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई जिससे उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर गांव लौटना पड़ा। अगस्त्यमुनि भीरी के पास मंदाकिनी नदी के पास पंवालिया में एक मकान पर रहने लगे। जबकि इसी स्थान से अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते रहे। पंवालिया में रहकर कवि ने करीब 1200 से अधिक रचनाएं लिखी। कवि ने अपनी रचनाओं में पहाड़, हिमालय, नदियों का सुन्दर वर्णन किया है। अंत में 14 सितम्बर 1947 को 28 वर्ष की अल्पायु में यह कवि दुनियां से चल बसे। कवि की कर्मस्थली पंवालिया की सभी भूमि को उनके परिजनों ने वर्ष 1978 में कृषि विभाग को दे दी थी। बता दें कि कवि के पंवालिया में स्मारक बनाने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने वर्ष 2017 में घोषणा की थी। पुरातत्व विभाग पौड़ी के संरक्षण सहायक अधिकारी अनिल नेगी ने बताया कि कवि चन्द्र कुंवर बर्त्वाल की कर्मस्थल पंवालिया में पहाड़ी शैली में स्मारक भवन के लिए 28 लाख का प्रस्ताव जिला योजना में भेजा गया था जिसमें अब तक 8 लाख की स्वीकृति मिली है। इसमें स्मारक एवं मूर्ति की स्थापना की जाएगी। अवशेष धनराशि स्वीकृत होने के बाद शीघ्र कवि का स्मारक भवन तैयार किया जाएगा। ताकि भविष्य आने वाली पीढ़ी कवि की रचनाओं से आत्मसात कर सके। (एजेंसी)

कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का फूंका पुतला

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन की नाकामी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। बुधवार को डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पंचायत चुनावों में पुलिस व प्रशासन के संरक्षण में अराजक तत्वों द्वारा सरेआम लोकतंत्र की हत्या का घृणित खेल खेला गया। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर वीरप्रताप सिंह, उपेंद्र रावत, तस्लीम जावेद, अनिल कुमार, अनूप कुमार आदि शामिल थे।

चॉक डाउन से तीन सौ से अधिक स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : पदोन्नति और वार्षिक तबादलों सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों की चॉक डाउन हड़ताल पौड़ी में बुधवार को भी रही। शिक्षकों की चॉक डाउन हड़ताल की वजह से जिले की करीब तीन सौ से अधिक स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है।

संघ के मंडलीय मंत्री डॉ. हेमंत पैन्यूली ने सचिव शिक्षा के पत्र को लेकर जिसमें शिक्षक आंदोलन नहीं कर सकते हैं को लेकर कहा है कि इससे अच्छा होता है कि शासन शिक्षकों की समस्या को हल करने संबंधी पत्राचार करता। मांगों को लेकर कई बार के आश्वासन मिले हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है। शिक्षकों के तबादले भी नहीं हो रहे है और इसको लेकर अभी तक कोई कार्यवाही विभाग स्तर पर नहीं हो पाई है। वहीं शिक्षक वार्षिक तबादलों की भी राह देख रहे है। मंडलीय उपाध्यक्ष सपना तोमर ने कहा कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के पक्ष में शिक्षक नहीं है। 70 फीसदी से अधिक स्कूलों में प्रभारी प्रधानाचार्य व्यस्थाएं देख रहे हैं।

महज उम्रदराज होना ही लाचार बहु–बच्चों को बेघर करने का लाईसेंस नहीः डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी जनता दर्शन में राजपत्रित पिता जो चलने फिरने में समथ है फिर भी व्हीलचेयर पर आकर डीएम से गुहार लगाई थी कि उनका बेटा बहु उनसे मारपीट करते हैं, उन्होंने भरण पोषण अधिनियम में वाद दाखिल कराने का अनुरोध किया जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया तथा फास्ट्रेक सुनवाई की गई।

पिता द्वारा अपने ही पुत्र, पुत्रवधु व 4 वर्षीय नौनिहाल पर भरणपोषण अधिनियम में वाद दायर कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना तथा दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत की जांच करने पर पाया कि पिता चल फिर सकने में सक्षम है तथा माता–पिता कुल 55 हजार आय अर्जित करते हैं तथा अपने अल्पवेतनभोगी लाचार बेटे के परिवार को निजी स्वार्थ के चलते झूठा वाद दायर घर से बेघर करना चाहता है।महज उम्रदराज होना ही बहु–बच्चों को बेघर करने का लाईसेंस नही है यह आज डीएम कोर्ट में पेश हुए वाद जिसमें डीएम ने निर्णय सुनाया है से सिद्ध हो गया है जहां एक राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त एक पिता ने फ्लेट की तृष्णा में निष्ठुर बन अपने ही अल्प वेतनभोगी बीमार बहु–बेटे व 4 वर्षीय पौती को बेदखल, घर से बेघर करने की योजना बनाई। अपने निजी स्वार्थ के चलते पिता अपने बहु–बेटे, नौनिहाल को घर से बेदखल करने की योजना बनाई तथा डीएम कोर्ट में भरणपोषण अधिनियम वाद डाला। डीएम न्यायालय में पेश इस मार्मिक प्रकरण ने आज प्रचलित विचारधारा को झंझोड़ कर ही रख दिया। डीएम ने मात्र 2 सुनवाई में स्थिति परखते ही लाचार दम्पति को कब्जा प्रतिस्थापित किया है। भरणपोषण

अधिनियम का दुरूपयोग करने वालों पर डीएम का फैसला नजीर बन गया है जिसमें वाद निर्णित, समाप्त; कार्यन्वित किया गया हैं। व्यथित बहु– बेटे के परिवार को बाह्य तत्व बुलाकर पिटवा चुका है जिस पर डीएम ने एसएसपी को भी दम्पति की सुरक्षा के निर्देश दिए है। इस वाद में असहाय के पक्ष में निर्णय से एक बार फिर कानून की आड़ में लाचारों का हक छिनने वालों पर जिला प्रशासन की न्यायप्रिय सख्त प्रशासन की छवि दर्शाता है। दोनों पक्षों को त्वरित सुन डीएम ने अपना फैसला सुनाते हुए पिता द्वारा दाखिल साजिश डीएम कोर्ट ने खंडित कर दी है।जिला मजिस्टेज्ट कोर्ट में दाखिल वाद संगीता वर्मा पत्नी जुगल किशोर वर्मा (माता–पिता) बनाम अमन वर्मा पुत्र नकरोंदा सैनिक कालोनी बालावाला में जहां राजपत्रित अधिकारी पद सेवानिवृत पिता जिसकी आय 30 हजार तथा माता की मासिक आय 25 हजार अपने अल्पवेतनभोगी बेटे अमन व उसकी पत्नी मीनाक्षी जिनकी कुल मासिक आय 25 हजार है पर भरणपोषण अधिनियम वाद पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए माता–पिता द्वारा दायर वाद को खंडित करते हुए लाचार दम्पति को डीएम ने किया कब्जा प्रतिस्थापित कर दिया है।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com